भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5400

जिसका उत्तर 25 जुलाई, 2019 को दिया जाना है।

.....

प्रमुख शहरों में जल संकट

5400. श्रीमती कनिमोझी:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि गर्मी के इस मौसम में चेन्नई भारी जल संकट का सामना कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश के अन्य प्रमुख शहरों में भी ऐसी ही स्थितियां हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में पानी की कमी को पूरा करने के लिए अल्पकालिक और दीर्घावधि उपाए किए गए हैं?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

(क) और (ख) केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) क्षेत्रीय स्तर पर पूरे ेश में सभी बड़े शहरों सहित निगरानी कुओं के नेटवर्क के माध्यम से समय-समय पर निगरानी करता है। दीर्घकालिक आधार पर गिरते जल स्तर के आकलन की दृष्टि से मानसून पूर्व जल स्तर आंकड़ों का संग्रहण सीजीडब्ल्यूबी द्वारा पूर्व मानसून 2018 में दशकीय औसत (2006-2017) की तुलना में किया गया है। जल स्तर आंकड़ों की समीक्षा से पता चलता है कि निगरानी किए गए कुओं के लगभग 56 प्रतिशत ने भूजल स्तर में गिरावट दर्ज की है। जिनमें से ज्यादातर की मात्रा 0-2 मीटर है। देश के कुछ शहरी क्षेत्रों अर्थात दिल्ली, चेन्नई, बंगलूरू, हैदराबाद, नासिक, पुणे, कानपुर, रांची, धनबाद, इंदौर, ग्वालियर, फरीदाबाद, चंडीगढ़, कोयमबटूर, मदूरै, देहरादून, जयपुर, जोधपुर, भुवनेश्वर, इलाहाबाद और लखनऊ के कुछ हिस्सों में यह गिरावट 4 मीटर से भी अधिक पाई गई है। चेन्नई में लगभग 85 प्रतिशत निगरानी किए गए कुओं में भूजल स्तर में गिरावट दर्ज की गई है, जिनमें से ज्यादातर के स्तर में गिरावट की मात्रा 0-2 मीटर है।

केंद्रीय जल आयोग साप्ताहिक आधार पर देश के 91 तालाबों के सक्रिय भंडारण स्थिति की निगरानी करता है और साप्ताहिक बुलेटिन जारी कर रहा है। इन 91 तालाबों की कुल सक्रिय भंडारण क्षमता 257.812 बीसीएम का लगभग 63 प्रतिशत है। दिनांक 18.07.2019 के जलाशय भंडारण बुलेटिन के आधार पर इन जलाशयों में उपलब्ध सक्रिय भंडारण 39.319 बीसीएम है जो इन जलाशयों की कुल सक्रिय भंडारण क्षमता का 24 प्रतिशत है। पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान भंडारण 32 प्रतिशत था तथा विगत 10 वर्षों की तदनुरूपी अवधि के दौरान इन जलाशयों की सक्रिय भंडारण क्षमता का औसत भंडारण 28 प्रतिशत था। तमिलनाडु में केंद्रीय जल आयोग 6 जलाशयों की सक्रिय भंडारण स्थिति की निगरानी करता है जिसकी कुल भंडारण क्षमता 4.23 बीसीएम है। दिनांक 18.07.2019 की जलाशय भंडारण बुलेटिन के आधार पर इन जलाशयों में कुल सक्रिय भंडारण 0.6 बीसीएम है जो इन जलाशयों की कुल सक्रिय भंडारण क्षमता का 14 प्रतिशत है। पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान भंडारण 74 प्रतिशत और विगत 10 वर्षों की तदनुरूपी अवधि के दौरान इन जलाशयों की सक्रिय भंडारण क्षमता का औसत भंडारण 39 प्रतिशत था। इस प्रकार देश के सा: -

तमिलनाडु में भंडारण स्थिति पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि से कम है और विगत 10 वर्षों की तदनुरूपी अवधि के दौरान औसत भंडारण भी कम रहा है।

(□) जल राज्य का विषय होने के कारण, जल संकट से निपटने के उपायों सहित जल संसाधनों, संवर्धन उपयों, संरक्षण, भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण और दक्षता पूर्ण प्रबंधन को प्राथमिक तौर पर संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करने की दृष्टि से केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। केंद्र सरकार ने देश के जल संकट को दूर करने के लिए भी अनेक कदम उठाए हैं।

जल शक्ति मंत्रालय को भारत सरकार द्वारा विगत के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय को एकीकृत करके जल संसाधन प्रबंधन को एक स्थान पर एकीकृत करने के उद्देश्य से सृजित किया गया है जिससे कि जल संबंधी मामलों से समग्र रूप से निपटा जा सके।

केंद्र सरकार ने जल संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एन□□□) का सूत्रपात किया है जो जल उपलब्धता को बढ़ाने के लिए जल की अधिकता के बेसिन में से कम जल वाले बेसिन में जल अंतरण पर □□□ □□□ □□

ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल की कवरेज को बढ़ाने के लिए इस मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग राज्यों के प्रयासों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) □□ माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

भारत सरकार ने अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) को चेन्नई सहित देशभर के 500 शहरों में 25 □□, 2015 □□ □□च वर्षों की अवधि के लिए शुरू किया है जिसका फोकस इन शहरों के बुनियादी शहरी अवसंरचना पर है। अमृत मिशन के तहत प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक जलापूर्ति है।

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेए□□□□) को शुरू किया है जिसका उद्देश्य खेतों तक जल की वास्तविक पहुंच क□ □□□□, सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत कृष्य क्षेत्र को विस्तारित करना, कृषि जल उपयोग दक्षता को बेहतर बनाना और सतत जल संरक्षण पद्धतियों इत्यादि को अपनाना है। वर्ष 2016-17 □□ □□□□ □□□□□□□□□-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआई□□□□) □□ □□□ □□□□99 □□□/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की अंतिम सिंचाई क्षमता 76.03 लाख हेक्टेयर है, जिसे राज्यों के साथ परामर्श करके उनकी प्राथमिकताएं तय की गई हैं जिनको दिसंबर, 2019 तक चरणबद्ध तरीके से पूरी किया जाना है।

केंद्रीय भूमि जल बोर्ड, भूमि जल संसाधनों के स्थायी विकास के लिए जलभृतों के मानचित्रण तथा जलभृत प्रबंधन योजनाओं के विकास हेतु एक राष्ट्र व्यापी कार्यक्रम "राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण तथा प्रबंधन (एनएक्यूयूआईएम)" को कार्यान्वित कर रहा है।

भारत सरकार ने जल शक्ति अभियान आरंभ किया है जो कि एक समयबद्ध अभियान है जिसका दृष्टिकोण मिशन मोड में है और जिसका उद्देश्य जल की कमी वाले ब्लॉकों में भूमि जल की स्थिति सहित जल की उपलब्धता में सुधार करना है।

केंद्र सरकार द्वारा भूमि जल के घटते स्तर को नियंत्रित करने तथा वर्षा जल संचयन/संरक्षण को बढ़ावा देने □□□□□□ □□ □□ प्रयासों/उपायों को निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध कराया गया है:-

http://mowr.gov.in/sites/default/files/Steps_to_control_water_depletion_Jun2019.pdf

*****